पटना के उच्च न्यायालय में

1990 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 2962

ने निर्णय लियाः 16.09.1999

याचिकाकर्ताओंः **सिद्धेश्वर प्रसाद और अन्य।**

बनाम

उत्तरदाताः **बिहार राज्य और अन्य।**

बिहार गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय(नियंत्रण का अधिग्रहण) अधिनियम्, 1976 - धारा 3(4)

सरदार पटेल मध्य विद्यालय, मीठापुर, पटना का अधिग्रहण करने तथा याचिकाकर्ताओं को वेतन और अन्य परिणामी लाभों का भुगतान करने के लिये रिट याचिका।

अधिग्रहण का मामला प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा विचार किया गया। उनके अनुसार, स्कूल के पास अपनी जमीन और भवन नहीं है और इसकी स्थापना का तारीख का पता लगाना संभव नहीं है।

निर्णित किया गया कि जिला समिति का निर्णय केवल अनुशंसित प्रकृति का है और राज्य सरकार के लिए बाह्यकारी नहीं है। अतः सरकार सरकार को अधिग्रहण का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

बिहार राज्य बनाम श्री चंद्रदीप राय(ए.आई.आर.1981 सुप्रीम कोर्ट 2017) पर भरोसा किया गया।

रिट याचिका को खारिज किया गया।

[पारा 2 और 11]

पटना के उच्च न्यायालय में

1990 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 2962

ने निर्णय लियाः 16.09.1999

याचिकाकर्ताओंः **सिद्धेश्वर प्रसाद और अन्य।**

बनाम

उत्तरदाताः **बिहार राज्य और अन्य।**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

एस.एन. झा, आफताब आलम और आर. एम. प्रसाद न्यायमूर्तिगण

निर्णय

एस. एन. झा, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका बिहार गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय (नियंत्रण का अधिग्रहण) अधिनियम, 1976 की धारा 3 (4) के तहत सरदार पटेल मध्य विद्यालय, मीठापुर, पटना का अधिग्रहण करने और याचिकाकर्ताओं को वेतन और अन्य परिणामी लाभों का भुगतान करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे क्रमशः स्कूल के सचिव, प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी हैं। जब 27-11-90 को इस न्यायालय की एक पीठ के समक्ष प्रवेश के लिए याचिका आई, तो स्कूलों के अधिग्रहण के लिए निर्देश जारी किए गए आदेशों पर भरोसा किया गया। पीठ ने यह वांछनीय माना कि इस सवाल पर कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश जारी किया जा सकता है, बिहार राज्य बनाम श्री चंद्रदीप राय मनु/एस.सी./0090/1981 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में एक विशेष पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाएःए. आई. आर. 1981. एस. सी. 2071, और तदनुसार मामले के अभिलेखों को एक

विशेष पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।इस तरह इस मामले को इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

3. बिहार गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय (नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1976 ('अधिनियम', संक्षेप में), बिहार राज्य में प्राथमिक शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए राज्य नियंत्रण के तहत गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अधिग्रहण का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। "अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत "प्राथमिक विद्यालय" को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ कक्षा OVII तक के ग्रेड का एक विद्यालय है जिसमें (i) जिला बोर्ड द्वारा स्थापित और प्रशासित एक विद्यालय और बिहार और उड़ीसा स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के तहत जिला परिषद, (ii) बिहार और उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 1922 के प्रावधानों के तहत नगर निगम बोर्ड द्वारा स्थापित और प्रशासित एक स्कूल और (iii) पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 द्वारा स्थापित और प्रशासित स्कूल।अधिनियम की धारा 3 (1) में 1-1-1971 से जिला बोर्ड, जिला परिषद, नगर बोर्ड और पटना नगर निगम द्वारा प्रबंधित ऐसे सभी स्कूलों के अधिग्रहित अधिग्रहण का प्रावधान है।

उपरोक्त के अलावा, अधिनियम में सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों और ऐसे प्राथमिक विद्यालयों के अधिग्रहण का भी प्रावधान है जो किसी भी सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा प्रशासित हैं।हालाँकि, ऐसे विद्यालयों के अधिग्रहण के लिए अलग-अलग तरीके और प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं।

4. इस स्तर पर अधिनियम की पूरी धारा 3 को उद्धृत करना उपयोगी होगा इसके नीचेः

> **3.** राज्य सरकार द्वारा गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का अधिग्रहण-(1) जिला बोर्ड, जिला द्वारा प्रबंधित प्राथमिक विद्यालय परिषद, नगर निगम बोर्ड और पटना नगर निगम और विस्तार और सुधार योजना के तहत खोले गए निगमों को 1 जनवरी, 1971 से राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया माना जाएगा।

(2) सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, जिनकी प्रबंध समितियों ने स्वैच्छिक रूप से सरकार को सौंपे गए विद्यालय का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा उस तारीख से लिया जाएगा जो इस उद्देश्य के लिए उप-धारा (4) में निर्दिष्ट जिला समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(3) किसी भी सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा प्रशासित प्राथमिक विद्यालय राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा उसमें निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से प्रभावी रूप से लिया जाएगा।

(4) (क) इनके अलावा अन्य प्राथमिक विद्यालयों के अधिग्रहण के संबंध में उप-धारा (1) और (3) में उल्लिखित प्रत्येक जिले में एक जिला समिति होगी जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों के अधिग्रहण की व्यवहार्यता की जांच करेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

(i) उप विकास आयुक्त/प्रशासक, जिला बोर्ड-अध्यक्ष।

(ii) जिला शिक्षा अधीक्षक-सचिव सदस्यः

(iii) जिला शिक्षा अधिकारी,

(iv) विद्यालयों के जिला निरीक्षक,

(v) संबंधित उप-मंडल के उप-मंडल शिक्षा अधिकारी, और

(vi) संबंधित विद्यालयों के उप निरीक्षक

(ख) राज्य सरकार समय-समय पर इनमें परिवर्तन कर सकती है - इस प्रकार गठित जिला समितियों के कर्मी।

5. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 2(सी) के तहत "सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय" को एक निजी स्कूल के रुप में परिभाषित किया गया है जो एक

प्रबंध समिति द्वारा प्रशसित होता है और जो अपने अस्तित्व से पहले सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहा है राज्य सरकार द्वारा लिया गया। अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत "गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय" शब्द को सरकार द्वारा प्राप्त एक निजी स्कूल के रुप में परिभाषित किया गया और जिसे कोई सरकारी अनुदान प्राप्त नही हो रहा है।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि अधिनियम की धारा 3 (2) "सहायता प्राप्त प्राथमिक" विद्यालयों को संदर्भित करती है। अधिनियम की धारा 3 (4) उप-धारा (1) और (3) में उल्लिखित विद्यालयों के अलावा अन्य प्राथमिक विद्यालयों को संदर्भित करती है। दूसरे शब्दों में, हालांकि धारा 3 (2) केवल सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित है, धारा 3 (4) के प्रावधानों के आधार पर वही गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अधिग्रहण के मामले में प्रक्रिया का पालन किया जाना है।विधानमंडल सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों और गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के बीच के अंतर से अवगत था, और इसलिए, "उप-धारा (1) और (3)" में उल्लिखित प्राथमिक विद्यालयों के अलावा अन्य प्राथमिक विद्यालय" अभिव्यक्ति की व्याख्या गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को भी शामिल करने के रूप में की जानी चाहिए। यदि विधायिका ने इरादा किया था अन्यथा, अधिनियम की धारा 3 (4) के तहत, इसमें "सहायता प्राप्त प्राथमिक" का उल्लेख होता। उप-धारा (1) और (3)" में उल्लिखित विद्यालयों के अलावा अन्य प्राथमिक विद्यालय नहीं। मेरे अनुसार, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के स्कूलों, अर्थात् सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अधिग्रहण के मामले में, धारा 3 (4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

7. पूर्व उद्धृत प्रावधानों से यह भी प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 3 प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अधिग्रहण के विभिन्न तरीकों की परिकल्पना की गई है। जबकि जिला बोर्ड, जिला परिषद, नगर बोर्ड और पटना नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित और प्रशासित स्कूल और विस्तार और सुधार योजना के तहत खोले गए स्कूल स्वचालित रूप से 1-1-1971 से प्रभावी हो जाते हैं, और किसी भी सार्वजनिक या निजी

उपक्रम द्वारा प्रशासित स्कूलों को निर्दिष्ट तिथि से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने वाली अधिसूचना द्वारा लिया जा सकता है, अन्य प्रकार के स्कूल जो उक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें उप-धारा (4), उप-धारा (4) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जा सकता है। प्रत्येक जिले के लिए समिति, जिसमें उप विकास आयुक्त/प्रशासक, जिला बोर्ड अध्यक्ष के रूप में और जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित जिलों/उप-शिक्षा के स्कूलों के उप-निरीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूलों के जिला निरीक्षक, उप-मंडल शिक्षा अधिकारी और संबंधित जिलों के स्कूलों के उप निरीक्षक इसके सदस्यों के रूप में होते हैं।राज्य सरकार को समिति के गठन में बदलाव करने का अधिकार है।

8. धारा 3 की उप-धाराओं (2) और (4) के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि - जिला समिति का लक्ष्य और उद्देश्य, वास्तव में एकमात्र कार्य अधिग्रहण की व्यवहार्यता की जांच करना और अधिग्रहण की प्रभावी तिथि निर्धारित करना है। जिला समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है।

9. याचिकाकर्ताओं के अनुसार एक बार जिला समिति एक पक्ष में हो जाती है विशेष विद्यालय की व्यवहार्यता की जांच करने के बाद, जैसा कि वर्तमान मामले में, विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित माना जाएगा और इस तरह के अधिग्रहण के लिए एक विशेष तिथि निर्धारित करने का एकमात्र विवेकाधिकार राज्य पर छोड़ दिया जाएगा।

10. रामनाथ राम बनाम बिहार राज्य 1995 (1) पी. एल. जे. आर. 359 में भी इसी तरह का तर्क दिया गया था बनाया कि जिला समिति का निर्णय विद्यालय को लेने के बराबर है। इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि जिला समिति केवल एक सिफारिश करने वाला निकाय है और व्यवहार्यता की जांच करने की शक्ति अधिग्रहण के अधिकार के समान नहीं है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 (2) में आने वाले "राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा" शब्दों को देखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आगे किसी अधिनियम का पालन करने की

आवश्यकता नहीं है। "आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना पर प्रकाशन" शब्दों के अभाव को राज्य सरकार को शक्ति का त्याग या समिति को शक्ति सौंपने के रूप में नहीं माना जा सकता है। राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य मनु/ बी. एच./ 0178/ 1990:1991 (1) पी. एल. जे. आर. 412 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम में धारा 3 की उप-धारा (1), (2) और (3) में उल्लिखित विद्यालयों के अलावा अन्य प्राथमिक विद्यालयों के अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है। विद्यालय के अधिग्रहण के मामले में राज्य सरकार की शक्ति एक कार्यकारी शक्ति है जिसका प्रयोग अकेले सरकार द्वारा किया जा सकता है।यह अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय सहित न्यायालयों के लिए सक्षम नहीं है। विद्यालय का प्रत्यक्ष अधिग्रहण करना।उच्च न्यायालय, एक उपयुक्त मामले में, केवल सरकार को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दे सकता है।

11. वर्तमान मामले में, यह प्रतीत होता है कि अधिग्रहण के संबंध में मामला इस न्यायालय के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन के आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा विद्यालय पर विचार किया गया था सी.डब्ल्यू.जे.सी. 1989 का सं. 4228 में निदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्कूल के पास अपनी जमीन और इमारत नहीं है और इसकी स्थापना की तारीख का पता लगाना संभव नहीं है।मेरे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि जिला समिति का निर्णय केवल अनुशंसित प्रकृति का है और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, यदि सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने अधिग्रहण के प्रस्ताव की व्यवहार्यता के संबंध में मामले पर प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया है, तो इस न्यायालय के लिए केवल जिला समिति के निर्णय के आधार पर स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने का कोई निर्देश जारी करना या याचिकाकर्ताओं को वेतन और अन्य परिणामी लाभों के भुगतान के लिए कोई निर्देश जारी करना संभव नहीं होगा।बिहार राज्य बनाम श्री चंद्रदीप राय (उपरोक्त) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां विद्यालय के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के भुगतान के संबंध में अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत

अधिसूचना द्वारा विद्यालय का अधिग्रहण नहीं किया गया है, और इसलिए संबंधित व्यक्ति ऐसे लाभों के हकदार नहीं हैं। ऐसे मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्कूल के उचित प्रबंधन या उन्हें वेतन के भुगतान के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हुए आदेश पत्र जारी करना उचित नहीं होगा।

12. विद्यालय के अधिग्रहण के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को तर्कपूर्ण आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं होने और अस्वीकृति का आधार बाहरी नहीं होने के कारण, मैं अपने आप को उनके पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश देने में असमर्थ पाता हूं।

13. इन परिसरों में, मैं इस रिट याचिका को खारिज कर दूंगा लेकिन बिना किसी आदेश के

लागत नहीं

आफताब आलम, न्यायमूर्ति

14. मैं सहमत हूँ।

आर. एम. प्रसाद न्यायमूर्ति

15. मैं सहमत हूँ।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।